हिन्दुस्तान • देहरादून • रविवार • 31 जनवरी 2021 •

आईएमए का सेव हेल्थ केयर इंडिया मूवमेंट, आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने का विरोध

प्राइवेट डॉक्टर कल से अनशन पर बैठेंगे

आईएमए

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

आयुर्वेद डाक्टरों को सर्जरी का अधिकार दिये जाने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने सेव हेल्थकेयर इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया है। जिसके तहत प्रदेश में सभी जिलों में एक से 14 फरवरी तक आईएमए से जुड़े निजी डाक्टर क्रमिक भूख हड़ताल पर रहेंगे।

शनिवार को चकराता रोड स्थित आईएमए ब्लड बैंक में आयोजित प्रेस वार्ता में आईएमए के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. डीडी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष डा. अरविंद शर्मा, प्रदेश सचिव डा. अजय खन्ना, ब्लड बैंक निदेशक डॉ. संजय उप्रेती ने अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिला शाखाओं को पूरा शेड्यूल भेज दिया गया है। सभी जगह की तारीख निर्धारित कर दी गई है। देहरादून और हल्द्वानी में पूरे चौदह दिन तक भूख हड़ताल रहेगी। सुबह दस से शाम पांच बजे तक डाक्टर अनशन करेंगे। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सचिवों की जिम्मेदारी दी गई है कि वह हर जिले में पांच से दस डाक्टर चयनित करें और जगह तय कर आंदोलन को आगे बढ़ाए। पदाधिकारियों ने कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने और आयुष पद्धति से सर्जरी करने पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन आयुष के नाम पर ऐलोपैथी चिकित्सा एनेस्थीसिया व दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिश्रित पैथी से इलाज करने से मरीजों की जान को खतरा होगा। पहले आयुष पद्धति में एनेस्थीसिया को विकसित करें। आयुष और मॉडर्न मेडिकल से गंभीर मरीज पर होने वाले रिएक्शन पर बिना रिसर्च किए सरकार ने सर्जरी की अनुमति दे दी। कहा कि यदि एलोपैथिक सर्जरी में मरीज को आयुष का लेप लगाया गया तो मरीज की मौत भी हो सकती है।

चकराता रोड स्थित आईएमए में ब्लड बैंक में जानकारी देते आईएमए पदाधिकारी।

मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों का आंदोलन आश्वासन पर टला

लोनिवि

देहरादून | विशेष संवाददाता

उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ने 76 निसंवर्गीय पद संवर्गीय करने समेत कई लंबित मांगों के हल का आश्वासन मिलने पर आंदोलन स्थगित कर दिया। विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता हरिओम ने इसका कार्यवृत्त जारी किया है।

दरअसल, एसोसिएशन के आह्वान पर राज्यभर के मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी आधे दिन के कार्यबहिष्कार पर थे। एक फरवरी से लोनिवि के सारे दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया था। मगर, शनिवार को प्रमुख अभियंता से वार्ता के बाद एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील

कार्यवृत्त जारी

- विभागाध्यक्ष से वार्ता के बाद एसोसिएशन ने लिया फैसला
- 76 पद संवर्गीय करने के लिए शासन भेजा जाएगा प्रस्ताव
- विभागाध्यक्ष ने एसोसिएशन से वार्ता का कार्यवृत्त जारी किया

कर्मचारियों पर बिना जांच कार्रवाई नहीं की जाएगी

प्रदेश महामंत्री दलीप सिंह बिष्ट ने बताया कि कर्मचारियों की कार्य कुशलता के लिए जल्द ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू करने एवं किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, बिना जांच नहीं करने और